Drought Prone Areas Programme (DPAP) being administered by this Ministry is drought proofing of areas affected by recurring droughts. The Programme is being implemented on a continuous basis and the Central financial assistance provided to the Programme States during 1997-98 is given below:—

(Rs. in lakhs)

Sl. No.	Name of the State	Central releases
1.	Andhra Pradesh	2292.495
2.	Bihar	115.130
3.	Gujarat	528.475
4.	Himachal Pradesh	69.500
5.	Jammu & Kashmir	112.500
6.	Karnataka	786.390
7.	Madhya Pradesh	892.545
8.	Maharashtra	1986.060
9.	Orissa	63.840
10.	Rajasthan	419.000
11.	Tamil Nadu	707.340
12.	Uttar Pradesh	842.055
13.	West Bengal	259.671
	TOTAL:	9075.001

(b) and (c) The Drought Prone Areas Programme (DPAP) was reviewed by a Technical Committee under the Chairmanship of Prof. C.H. Hanumantha Rao, Former Member, Planning Commission. In its Report submitted in April, 1994, the Committee made the following important recommendations:

(i) all the area development programmes including Drought Prone Areas Programme (DPAP) be implemented exclusively on watershed basis and in a project mode.

(ii) The watershed development projects, each of a size of about 500 hectares, be planned, executed and maintained by people's organisations specifically set-up for the purpose under the technical and financial support of the Government.

(iii) To make more financial provisions for watershed development, all financial outlays of Drought Prone Areas Programme (DPAP), Desert Development Programme (DDP) and Integrated Wastelands Development Programme (IWDP) and 50% of Employment Assurance Scheme (EAS) be utilised on these watershed development projects.

(d) question does not arise.

राज्यों में सर्वेक्षण और बंदोबस्त सम्बन्धी कार्य

3951. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में सर्वेक्षण और बंदोबस्त संबंधी कार्य शुरू किये हैं;

(ख) यदि हां, तो सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक इस संबंध में त्रिपुरा और मध्य प्रदेश में क्या प्रगति हुई है;

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान त्रिपुरा और मध्य प्रदेश में इस योजना के अंतर्गत कितने ग्रामों को शामिल किया गया है; और

(घ) भूमि संबंधी अभिलेखों को यथाशीघ्र पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटिल): (क) भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) की प्रवेश संख्या 45 के अनुसार सर्वेक्षण तथा बंदोबस्त कृषि राज्य के विषय हैं तथा इसकी स्थायी तथा निरंतर जिम्मेवारी राज्य के राजस्व विभागों की है। इस विषय में उन्नत प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए भारत सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करती है तथा राज्य सरकारों से इससे जुड़े कार्यों में ज्यादा पहल करने का आग्रह करती है।

(ख) और (ग) इस सम्बन्ध में मध्य प्रदेश तथा त्रिपुरा के राज्य सरकारों द्वारा की गई प्रगति निम्नानुसार है:—

31.5.98 को सर्वेक्षण तथा बंदोबस्त कार्य के अंतर्गत मध्य प्रदेश में, राज्य के 76,603 गांवों में से 30,957

गांवों के नक्शे तथा अभिलेख पूर्ण रूप से तैयार कर लिए गए थे। सातवीं तथा आठवीं योजना के दौरान राज्य में सर्वेक्षण तथा बंदोबस्त कार्यों की प्रगति को दर्शाने वाला विवरण निम्नानुसार है:—

राज्य ने सातवीं योजना के अंत तक सर्वेक्षण तथा बंदोबस्त कार्यों को खंडुआ तथा दुर्ग जिले के 2896 गांवों में पूरा कर लिया था। शिवपुरी, दमोह, पन्ना, शिवनी, सागर, जबलपुर, कटनी, मंडला, दिन्दौरी, झाबुआ, उज्जैन, कांकेर, कोरिया (बैकुंठपुर) नामक 13 जिलों के 15,903 गांवों में कार्य अधूरे थे जबकि बहुत से जिलों में कार्यक्रम जारी था।

आठवीं योजना के दौरान राज्य ने उपर्युक्त 13 जिलों के 15,903 गांवों में सर्वेक्षण तथा बंदोबस्त कार्य पूरा कर लिया था। 22 अन्य जिलों के 10,992 गांवों में कार्य अनुप्रमाणन की अवस्था तक पूरा कर लिया गया था। बहुत से अन्य जिलों में कार्य जारी था।

त्रिपुरा राज्य में 1978 से संशोधन नामक सर्वेक्षण तथा बंदोबस्त के कार्य शुरू किए गए हैं तथा सातवीं योजना अवधि तक सर्वेक्षण तथा बंदोबस्त कार्य में निम्नांकित प्रगति हुई है:—

(क)	बुझारत	—	546 गांव
(ख)	अनुप्रमाणन	—	508 गांव
(ग)	प्रारूप प्रकाशन	—	496 गांव
(घ)	अंतिम प्रकाशन	—	464 गांव

आठवीं योजना अवधि के दौरान राज्य सरकारों द्वारा सूचित सर्वेक्षण तथा बंदोबस्त कार्य की स्थिति निम्नानुसार है:—

(क)	बुझारत	—	195 गांव
(ख)	अनुप्रमाणन	—	212 गांव
(ग)	प्रारूप प्रकाशन	—	219 गांव
(घ)	अंतिम प्रकाशन	—	238 गांव

(घ) भू अभिलेखों की तैयारी तथा अद्यतन करने का काम एक सतत प्रक्रिया है। भू-अभिलेखों को अद्यतन बनाने के काम को पूरा करने तथा उसे एक कम्प्यूटरीकृत व्यवस्था तथा रख-रखाव के अंतर्गत लाने के लिए समय-समय पर राज्य सरकारों को सलाह दी गई है। इस सम्बन्ध में भारत सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्र द्वारा प्रायोजित दो योजनाओं (1) राजस्व प्रशासन तथा भू-अभिलेखों के अद्यतनीकरण को सुदृढ़ करना तथा (2) भू-अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। इन योजनाओं के अंतर्गत क्रमशः 153.69 करोड़ रुपये तथा 84.62 करोड़ रुपये राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उपलब्ध कराये गए।

Assessment of E.A.S. in Maharashtra

3952. MISS SAROJ KHAPARDE: Will the Minister of RURAL AREAS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether Government have assessed the success of Employment Assurance Scheme (EAS) in Maharashtra;

(b) if so, the findings thereof;

(c) if not, the reasons therefor;

(d) whether all the villagers want employment under EAS Cards in the State particularly in the Vidarbha region;

(e) if not, the reasons therefor; and

(f) the steps taken by Government to make EAS successful in Maharashtra?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF RURAL AREAS AND EMPLOYMENT (SHRI BABAGOUDA PATIL): (a) Employment Assurance Scheme is closely monitored for all the States including Maharashtra. The monitoring mechanism include review with the State Secretaries of Rural Development, review in the annual workshop of the project Directors of DRDAS, monthly and annual progress reports etc. The States also review the implementation of the scheme at their level. The Government of Maharashtra have reported that EAS is being implemented successfully. The progress of the scheme is assessed time to time and suitable instructions are given for effective implementation.

(b) The Maharashtra government have reported that the programme is very effective and fruitful. It has helped in providing gainful employment during the Lean Agriculture Season and in creation of economic infrastructure and community assets for sustained employment.